ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

लुप्त हो रहे हैं खैर के जंगल

रविवारीय, 26 जनवरी - 01 फरवरी 2020 वर्ष- एक, अंक-25, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्य 2 रूपये

ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से आप सभी पाठकों को गणतंत्र दिवस एवं वसंतपंचमी की असीम शुभकामनायें

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

खिलाड़ी देश और राज्य के धरोहर हैं: हेमन्त सोरेन

रांची : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खेलो इंडिया गेम्स 2020 में भाग लेने गई झारखण्ड के खिलाड़ियों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कड़ी निंदा की है।मुख्यमंत्री ने असम के मुख्यमंत्री से इस गम्भीर मामले पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा खिलाड़ी देश और राज्य के धरोहर हैं। हमें इसका ध्यान रखना चाहिए।

रेलवे सुरक्षा बल का विशेष अभियान चला

वर्ष 2019 में रांची रेल मंडल के रेल सुरक्षा बल द्वारा अनधिकृत रूप से रेल रिजर्वेशन टिकट का कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया इस अभियान के तहत 72 मुकदमे दर्ज किए गए तथा 79 टिकट की कालाबाजारी करने वाले दलालों को गिरफ्तार किया गया ,जिनसे कुल 1503 रेल टिकट जब्त की गई`जिसमें यात्रा नहीं की गई ऐसी 220 टिकटें थी तथा जिन पर यात्रा की गई ऐसी 1283 टिकटें थी। यह रेलवे अधिनियम 143 के अंतर्गत गंभीर अपराध है।

जिन टिकट पर यात्रा नहीं की गई थी उनकी कुल कीमत 3 लाख 46 हजार 296 रूपये थी जिन टिकट पर यात्रा की गई थी उनकी कुल कीमत 19 लाख 32 हजार 519 रूपये है। गहन जांच करने के पश्चात 377 अनाधिकृत आ-ईडी जब्त किए गए और उनमें से 371 अनाधिकृत आईडी को आईआरसीटीसी के द्वारा बंद किया गया। जिन 79 टिकट दलालों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से छह दलालों को कोर्ट द्वारा 58 हजार 500 रूपये दंड दिया गया और बाकी दलालों की जांच अभी जारी है ।

केंद्र सरकार ने नल से जल और अटल भूजल योजना की शुरुआत की है, विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार इनका आवंटन बढ़ा सकती है

साफ पानी पहुंचाने पर होगा फोकस?

संवाददाता

एक फरवरी 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब आम बजट 2020-21 पेश करेंगी तो पूरी संभावना है कि पानी पर उनका खास फोकस होगा। खासकर जल सुरक्षा उनके बजट का अहम हिस्सा हो सकता है।

देश में जल संकट से निपटने के लिए पिछले कुछ महीनों में 'नल से जल' और 'अटल भूजल योजना' जैसी योजनाएं शुरू की गईं। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार इन योजनाओं के लिए धन आवंटित करेगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की योजना के बारे में स्पष्ट रास्ता बताएगी।

पुणे स्थित एडवांस सेंटर फॉर वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट (एसीडब्ल्यूएडीएएम) के कार्यकारी निदेशक और सचिव हिमांशु कुलकर्णी ने कहा कि

सरकार को जल से संबंधित योजनाओं का फंड एक ही कार्यक्रम में नहीं मिलाना चाहिए। अगर ऐसा किया भी जाता है, तो भी कार्यक्रम के अलग-अलग घटकों को परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि जल प्रबंधन और प्रशासनिक घटकों को आपस में जोड़ा जा सके, जिसमें कृषि, उद्योग और शहरों की पानी की जरूरतों को भी शामिल हों।

कुलकर्णी ने कहा कि सभी के लिए नल से जल यानी पाइप के जरिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य हासिल करना है या बल्क आपूर्ति की जानी है तो बेहतर प्रबंधन से ही यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। सरकार ने हाल ही में अटल भूजल योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इस योजना में एक प्रावधान है जिसके तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को अधिक धन आवंटित किया जाएगा।

भारत में पहली बार विशेष रूप से भूजल पर केंद्रित अटल भूजल योजना शुरू हुई है। अब तक भूजल से जुड़े कई कार्यक्रम थे, लेकिन सब अप्रत्यक्ष तौर पर भूजल प्रबंधन की बात करते थे। वो या तो रिचार्ज, वाटरशेड, या बड़े पैमाने पर सिंचाई कार्यक्रम थे, लेकिन वे सीधे-सीधे भूजल की बात नहीं करते थे, जैसा कि, अटल भूजल योजना में की गई है। यह पहली बार है जब देश के पास अपना भूजल के लिए समर्पित कार्यक्रम है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि इसे किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा।

रांची दौरे पर पहुंचे, केंद्र के सेक्रेटरी फूड एवं सप्लाई

- मुख्य सचिव श्री डीके तिवारी से वन नेशन वन कार्ड को लेकर हो चुकी है मुलाकात
- पीडीएस दुकानों और प्रोक्योरमेंट सेंटर का किया दौरा

संवाददाता

रांची : शुक्रवार को रांची पहुंचे रविकांत, सचिव खाद्यान्न एवं आपूर्ति विभाग, भारत सरकार ने शनिवार को रांची के लोकल पीडीएस दुकानों एवं प्रोक्योरमेंट सेंटर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पीडीएस दुकानदारों के द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्न वितरण की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने पीडीएस दुकानदारों से वन नेशन वन कार्ड के क्रियान्वयन में सहयोग देने को कहा। जिससे कि किसी भी लाभुक को सरकार द्वारा दिए जाने लाभ को प्राप्त करने में परेशानी ना हो।

इसके अतिरिक्त उन्होंने हटिया स्थित रेल साइड वेयर हाउस का भी दौरा किया एवं वहां मौजूद सुविधाओं की जानकारी ली।

पूर्व में रविकांत ने वन नेशन वन कार्ड को लेकर झारखंड के मुख्य सचिव डी के तिवारी से भी मुलाकात की थी साथ ही राज्य के उच्चाधकारियों के साथ भी उन्होंने इस सबंध में बैठक की थी। बैठक के दौरान उन्होंने वन नेशन वन कार्ड को क्रियान्वित करने हेतु जरूरी निदेश भी दिए थे।

उपायुक्त रांची को उत्कृष्ट कार्य के लिये मिला सम्मान

संवाददाता

- मुख्य अतिथि माननीया राज्यपाल ने उपायुक्त, रांची को चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य हेतु किया सम्मानित।
- लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव–2019 के दौरान मतदाता जागरुकता एवं शांतिपूर्ण, निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराने के लिए मिला सम्मान।
- उपायुक्त ने कहा, ''यह सम्मान पूरी टीम रांची के सहयोग से संभव हुआ, यह सम्मान उन सभी कर्मियों के लिए।

रांची :शनिवार, दिनांक-25.01.2020 को पूरे देशभर में राष्ट्रीय मतदाता दिवस-2020 का आयोजन किया गया। इस विशेष मौके पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में माननीया राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची को माननीया राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त फर्स्ट टाइम वोटर, वरिष्ठ मतदाताओं का सम्मान सहित नए मतदाताओं के बीच मतदाता फोटो पर्ची वितरित की गई। शनिवार को रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर माननीया राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा चुनाव 2019 एवं विधान सभा चुनाव-2019 के दौरान मतदाता जागरुकता के लिए विशेष आयोजन करने एवं पूरे जिला में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

वर्ष 2019 में पूरे देशभर में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के ठीक पश्चात झारखण्ड में विधानसभा चुनाव भी संपन्न कराया गया। इन दोनों ही निर्वाचन कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए राज्य के तीन जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाना था। इनमें उपायुक्त, रांची के अलावा बोकारो एवं हजारीबाग़ को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड श्री विनय चौबे ने कहा कि स्वीप के तहत पूरे राज्य में मतदाता जागरुकता पर विशेष जोर देकर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका लाभ भी मिला। सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं।

हम सपनों का झारखंड बनायेंगे : सीएम

रांची : हमें कई चुनौतियां मिली हैं। इतिहास एक बात का गवाह है कि हम चुनौतियों से हमेशा दो चार करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहे हैं क इस बार भी चुनौतियों को स्वीकारा है। इसे एक अवसर के रूप में लिया है। अभी तो शुरुआत है। कई काम किए जाने हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ विकास योजनाओं को पूरा करेंगे ताकि हम झारखण्ड के लोगों के सपनों का झारखंड बना सकें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री दुमका में स्विमिंग पुल के उद्घाटन कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झा-रखंड के विकास की खातिर जहां बात रखने की जरूरत होगी। उस मंच पर उसे रखा जाएगा। जहां काम करने की जरूरत है। वहां सिर्फ काम पर फोकस होगा। सरकार लोकलुभावन वादों में विश्वास नहीं करती बल्कि अपने इरादों को हकीकत में बदलने की बात करती है। दुमका पूरे राज्य की नाक, इसकी इज्जत पर आंच न आये मुख्यमंत्री ने कहा कि उपराजधानी दुमका उनकी कर्मभूमि रही है।

विस्थापितों की समस्याओं के निष्पादन के लिए सीसीएल प्रतिबद्ध -सीएमडी सीसीएल

संवाददाता

सीसीएल में खनन - सह - पुर्नस्-थापना विकास समिति की बैठक

रांची : सीसीएल मुख्यालय दरभंगा हाउस स्थित ''सीसीएल भवन'' में सीसीएल कमांड क्षेत्रों में स्-थापित खनन - सह - पुनस्र्थापन विकास समिति की बैठक का आयोजन सीएमडी गोपाल सिंह की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में निदेशक तकनीकी (संचालन) वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) भोला सिंह, महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) वी.के. शुक्ला, महाप्रबंधक/सीएमडी के तकनीकी सचिव एम. रजिमवाले, महाप्रबंधक (प्रशासन) विमलेन्-दू कुमार, महाप्रबंधक (विधी) पार्थो भट्टाचार्यजी, वरीय प्रबंधक (कार्मिक) एस.के. झा, वरीय प्रबंधक (कार्मिक) संजय सिन्हा, वरीय प्रबंधक (कार्मिक) आर.आर. शर्मा सहित सैकड़ो समिति सदस्य व अधिकारीगण उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए सीमएडी गोपाल सिंह ने कहा कि सीसीएल विस्थापितों की समस्याओं को नियमानुसार समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि सीसीएल कमांड क्षेत्र के हर परिवार का प्रत्येक व्यक्ति सीसीएल वृहद परिवार का सदस्य है और सीसीएल की प्रगति में भागीदार है। समस्याओं के समाधान के लिए हर व्यक्ति को जागरूक रहते हुये अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा। .....शेष पेज 3पर

रेलवे अतिरिक्त कोच की सुविधा देगा

रांची : यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को मद्देनजर रखते हुए रांची रेल मंडल द्वारा निम्नलिखित ट्रेनों में स्थायी तौर पर अतिरिक्त कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जीससे यात्रियों को आरक्षण मिलने एवं यात्रा करने मे सुविधा होगी।

दिनांक 01.04.2020 से ट्रेन संख्या 18626 हटिया-पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस में तथा दिनांक 02.04.2020 से ट्रेन संख्या 18625 पूर्णिया कोर्ट - हटिया एक्सप्रेस मे एसी-2 का एक कोच एवं एसी-3 के दो अतिरिक्त कोच स्थायी तौर पर लगाए जायेंगे।दिनांक 01.04.2020 से ट्रेन संख्या 18635/18636 रांची - सासाराम - रांची मे एसी चेयर कार के तीन अतिरिक्त कोच स्थायी तौर पर लगाए जायेंगे।।

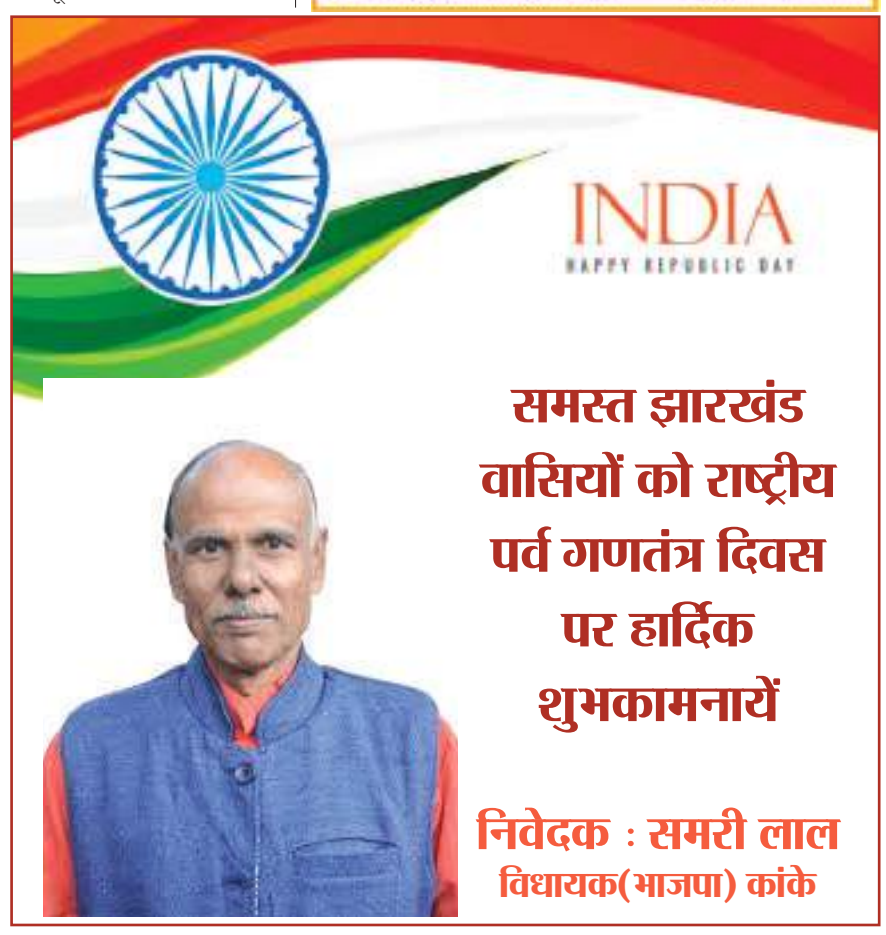

देशबंधु आई0टी0आई, कमड़े
झारखण्ड मोटर ड्राईविंग एण्ड ट्रेनिंग स्कूल, कमड़े
कलावति स्कूल स्कूल ऑफ फार्मेसी, कमड़े एवं डी0ए0भी शिक्षा दीप परिवार
की ओर से समस्त झारखण्ड वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं।
नामांकन जारी है,
निदेशक - शिवनन्दन पाठक, मो-9304058912

BOOK INDIA
DEALS IN SCHOOL BOOKS & STATIONARY
BRANDED BOOK REASONABLE PRICE
LEADING PUBLISHERS
- Top High Quality Books
- C.B.S.E., NCERT,ICSE & JAC Board
- 365 Days Services

SPECIALIST IN Pvt. School Books/Play School Books/Childrens Books

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध
Sahay Compound, St. Anne's Girls School Lane, Tharpakhna, Ranchi Ph. : 9199365691,7050112727,0651-6522703

समस्त झारखंडवासियों को छात्र क्लब ग्रुप, विश्वकर्मा युवा सुरक्षा मंच एवं कपिल फाउण्डेशन की ओर से 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं
निवेदक : संतोष कुमार, दीपक राणा, सुनील कुमार साहु, मोहन जायसवाल,अनीता कुमारी, शीला साहु

संस्थापक अध्यक्ष : शिव किशोर शर्मा

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

संपादकीय

चीन से फैलता कहर

चीन में फैले कोरोना वायरस से सारी दुनिया भयभीत है। वहां हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। चीन में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चार शहरों में लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। लेकिन क्या दुनिया में भी इस वायरस की वजह से हेल्थ इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, इस मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मैराथन बैठक के बाद कहा गया कि अभी तक इस विषाणु की न तो गंभीरता का पता चला है न ही स्त्रोत और संक्रमण को लेकर ठोस जानकारी लगी है, इसलिए चीन में कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी को स्थिति को फिलहाल वैश्विक आपातकाल यानि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता की स्थिति (पीएचईआईसी) न माना जाए।अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक की आपात समिति ने जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में चली बैठक के बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने यह घोषणा की। आपात समिति के प्रधान डीडीएर हौसिन ने कहा कि आपात समिति के सदस्यों के बीच इस मामले पर काफी मतभेद हैं। आधे सदस्यों का मानना था कि यह आपात स्थिति है, क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या और इसका फैलाव काफी अधिक है। बाकी सदस्यों ने कहा कि इस संक्रमण का फैलाव चीन के बाहर काफी सीमित है और चीन का प्रशासन इससे निपटने के लिए सही निर्णय ले रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति घोषित करना इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है और फिलहाल ऐसा करना जल्दबाजी होगी।

> डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेडरोस एडहानोम घेब्रेयासस इस समिति के निर्णय के बाद ही आपात स्थिति की घोषणा करने वाले थे। संयोगवश, इस बैठक के ठीक पहले सिंगापुर और वियतनाम से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए थे, इस वायरस को अमेरिका, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग में भी पाया गया। ब्रिटेन में इस वायरस के संभावित मरीजों की पड़ताल चल रही है। डब्लूएचओ के मुताबिक अब तक 584 मामलों को पुष्टि हो चुकी है।

डीजल से होने वाले प्रदूषण से बढ़ रहे हैं निमोनिया के मामले

आमतौर पर स्वस्थ इंसान के नाक और गले में मौजूद रहने वाला एक हानिरहित न्यूमोकोकल बैक्टीरिया, प्रदूषण के कारण निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का रूप धारण कर लेता है

विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि वायु प्रदूषण हर साल करीब 70 लाख लोगों की जान ले लेता है। जिनमें से 7 फीसदी मौतें निमोनिया के कारण होती हैं। वहीं दुनिया की 37 फीसदी आबादी उन क्षेत्रों में रहती है जहां वायु प्रदूषण का स्तर डब्ल्यूएचओ द्वारा तय मानक से काफी अधिक है। वहीं दूसरी ओर दुनिया भर में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण डीजल से होने वाला उत्सर्जन है। जिसमें कालिख और एरोसोल प्रमुखता से होते हैं जोकि राख, धातु के कण, सल्फेट्स और सिलिकेट्स से बने होते हैं। डीजल से जो प्रदूषण होता है, उसमें बहुत ही महीन कण उत्सर्जित होते हैं। उसके संपर्क में आने से लोगों में न्यूमोनिया होने कि सम्भावना कहीं अधिक बढ़ जाती है।

गौरतलब है कि न्यूमोकोकल संक्रमण (निमोनिया), बीमारियों की एक व्यापक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है जो स्ट्रैपटोकोकस निमोनिया (एस. निमोनिया / निमोकोकस) की वजह से होता है। मूलतः स्ट्रैपटोकोकस जीवाणु निमोनिया और मैनिंजाइटिस बीमारी का सबसे आम कारण है। इसके साथ ही यह दुनिया भर में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों और बुजुर्गों में संक्रामक रोग से होने वाली मौतों का एक प्रमुख कारण है।

बैक्टीरिया को खतरनाक बीमारी में बदल देता है प्रदूषण

आश्चर्य की बात है कि यह बैक्टीरिया अधिकांश स्वस्थ लोगों में नाक और गले में मौजूद रहता है, और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता न ही किसी प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन अगर यही बैक्टीरिया फेफड़े और रक्त तक पहुंच जाता है, तो कई हानिकारक बीमारियों का कारण बनता है। आखिर नुकसान न करने वाला यह बैक्टीरिया कैसे एक जानलेवा बीमारी का रूप ले लेता है इसे समझने के लिए लिवरपूल, क्वीन मैरी विश्वविद्यालय, लंदन और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के शोधकर्ताओं द्वारा एक व्यापक अध्ययन किया गया है। जोकि जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। जिसमें उन्होने न्यूमोकोकल के विकास में डीईपी (डीजल से होने वाले प्रदूषण) और उसकी भूमिका की भी जांच की है।

कोरोना वायरस :विश्व में लग सकती है इमरजेंसी?

वनजोत कुमार

कोरोना वायरस की वजह से चीन में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने कहा है कि दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी लगाना जल्दबाजी होगी

चीन में फैले कोरोना वायरस का कहर बढ़ रहा है। वहां हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। चीन में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चार शहरों में लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है। लेकिन क्या दुनिया में भी इस वायरस की वजह से हेल्थ इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, इस मुद्दे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की मैराथन बैठक के बाद कहा गया कि अभी तक इस विषाणु की न तो गंभीरता का पता चला है न ही स्त्रोत और संक्रमण को लेकर ठोस जानकारी लगी है, इसलिए चीन में कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी को स्थिति को फिलहाल वैश्विक आपातकाल यानि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंता की स्थिति (पीएचईआ-ईसी) न माना जाए।अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियामक की आपात समिति ने जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में चली बैठक के बाद अंतरराष्ट्रीय मीडिया के सामने यह घोषणा की। आपात समिति के प्रधान डीडीएर हौसिन ने कहा कि आपात समिति के सदस्यों के बीच इस मामले पर काफी मतभेद हैं। आधे सदस्यों का मानना था कि यह आपात स्थिति है, क्योंकि संक्रमित लोगों की संख्या और इसका फैलाव काफी अधिक है। बाकी सदस्यों ने कहा कि इस संक्रमण का फैलाव चीन के बाहर काफी सीमित है और चीन का प्रशासन इससे निपटने के लिए सही निर्णय ले रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए आपात स्थिति घोषित करना इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है और फिलहाल ऐसा करना जल्दबाजी होगी। डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेडरोस एडहानोम घेब्रेयासस इस

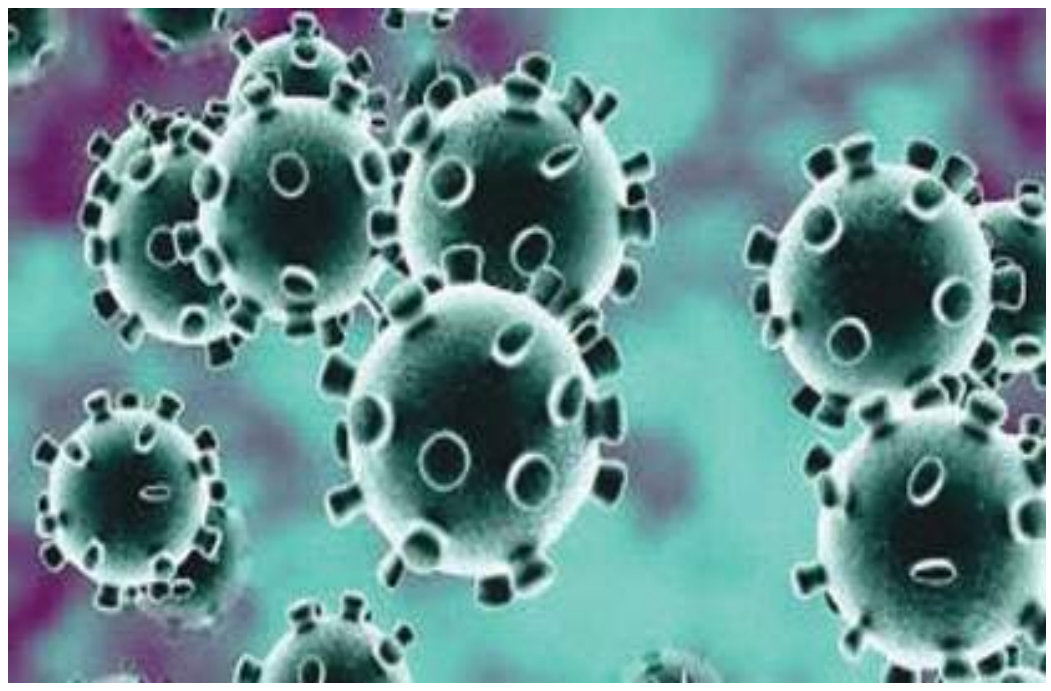

समिति के निर्णय के बाद ही आपात स्थिति की घोषणा करने वाले थे। संयोगवश, इस बैठक के ठीक पहले सिंगापुर और वियतनाम से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए थे, इस वायरस को अमेरिका, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान और हांगकांग में भी पाया गया। ब्रिटेन में इस वायरस के संभावित मरीजों की पड़ताल चल रही है। डब्लूएचओ के मुताबिक अब तक 584 मामलों को पुष्टि हो चुकी है जिनमें से 17 मामले में मरीज की मृत्यु हो गई।

घेब्रेयासस ने कहा कि डब्लूएचओ के द्वारा खतरे का मूल्यांकन किया गया और इससे पता चला कि चीन के लिए वायरस बेहद खतरनाक है और बाकी दुनिया के लिए यह स्थिति कुछ कम खतरनाक है। यह चीन के लिए आपात स्थिति है, लेकिन विश्व के लिए ऐसी स्थिति नहीं बनी कि आपातकाल घोषित किया जाए। हालांकि, ऐसी स्थिति बन भी सकती है। उनसे जब चीन में चार शहरों को बंद करने की घटना पर टिप्पणी करने को कहा गया तो महानिदेशक ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया और कहा कि डब्लूएचओ केवल देशों को तथ्यात्मक और वैज्ञानिक सलाह देता है। अब यह उस देश पर निर्भर करता है कि वो उन सलाहों पर क्या कदम उठाते हैं। कुछ देर पहले डब्लूएचओ के वरिष्ठ अधिकारी ने एसोसिएट प्रेस को साक्षात्कार देते हुए कहा था कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक शहर को बंद कर रखने की बात उन्होंने कभी नहीं सुनी और इसका क्या असर होगा, इसके बारे में भी उन्हें कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। घेब्रेयासस से पूछा गया कि क्या चीन ने सीवियर एक्यूट रेसपिरेटिरी सिंड्रोम (एसएआरएस) के दौरान हुई गलतियों से कुछ सीखा है? सांस संबंधी इस बीमारी ने 2003 में चीन में 800 लोगों की जान ले ली थी और यह बीमारी भी कोरोना वायरस के द्वारा फैली थी। इसके जवाब को घुमाते हुए उन्होंने कहा कि सक्षम देश अपनी बेहतरी के लिए अपनी सोच के मुताबिक अच्छे से अच्छे कदम उठाते हैं। कुल मिलाकर घेब्रेयासस स्वीकारते हैं कि इस वायरस का स्त्रोत तय नहीं है कि वह चमगादड़ है, या सांप या फिर कोई और जानवर। यहां तक को इस रोग की गंभीरता का अंदाजा भी अभी तक नहीं हो पाया है। डब्ल्यूएचओ ने चीन को लेकर यात्रा संबंधी रोक भी नहीं लगाई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मानव पलायन का केंद है जहां करोड़ों लोग चंद्र नव वर्ष मनाने जनवरी 25 को जा रहे हैं। हालांकि, यह कहा गया है कि यात्रियों को देश में आने से पहले उनकी सख्त निगरानी की जाए। डब्लूएचओ का कहना है कि इंसानों के बीच आपस में इस विषाणु के संचरण की भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने चीन को वायरस से संबंधित नमूने वैश्विक वैज्ञानिक समाज से साझा करने के लिए धन्यवाद कहा है। हालांकि, जब उनसे यह सवाल पूछा गया कि क्या चीन ने संक्रमण की अलग-अलग स्थिति के नमूनों को साझा किया है, जिससे कि विषाणु का अलग-अलग स्तर पर शरीर पर प्रभाव को जाना जा सके। सवाल के जवाब में माइक रयान कहते हैं कि एक दिन पहले ही यह सब साझा किया गया।

उल्लेखनीय है कि चीन में विषाणु संक्रमण का पहला मामला 23 दिन पहले 31 दिसंबर को सामने आया था। संक्रमण का चक्र जानना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे विषाणु का शरीर पर अलग-अलग स्तर पर प्रभाव आंका जा सकता है और विषाणु को समझने में मदद मिलती है।

रयान ने कहा कि अब हमारे पास बीमारी की शुरुआत से लेकर अब तक का आंकड़ा है, जिससे इसके विभिन्न स्तरों को जांच की जा सकेगी। हालांकि उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि वैश्विक स्तर पर इस जानकारी को कब साझा किया जाएगा। इस विषाणु का अभी तक नाम भी नहीं तय हुआ, क्योंकि ऐसा करने के लिए डब्लूएचओ के विशेषज्ञों को समय नहीं मिला। एक विशेषज्ञ के मुताबिक नोवेल कोरोना वायरस (कोरोना वायरस का नया प्रकार) एक सही नाम है और वैज्ञानिक समाज इस नाम के साथ ही काम कर रहा है। डब्ल्यूएचओ ने चीन को सुझाया है कि वे जानकारी साझा करने में पारदर्शी रहे, ताकि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े दुनिया भर के विशेषज्ञ इससे बचाव के लिए आगे आ सकें। साथ ही, डब्ल्यूएचओ ने विश्व के दूसरे देशों को सलाह दी है कि वे सतर्क रहें। घेब्रेयासस ने दोबारा आश्वस्त किया कि अगर जरूरत पड़ी तो आपात समिति की अगली बैठक कभी भी आयोजित की जाएगी, यहां तक कि सिर्फ एक दिन की पूर्व सूचना पर यह बैठक बुलाई जा सकती है। ●

ओजोन क्षरण वाले एचसीएफसी141-बी आयात पर रोक

सरकार के आंकड़े और दावे से उलट शोध पत्र यह इशारा करते हैं कि भारत में एचसीएफसी 141-बी से उत्सर्जन पहले से ही बहुत कम है।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (एचसीएफसी)झ 141-बी का आयात एक जनवरी, 2020 से पूरी तरह से बंद कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि 141-बी एचसीएफसी का इस्तेमाल मुख्य रूप से आयात के जरिए फोम इंडस्ट्रीज के जरिए किया जाता है। सरकार का दावा है कि भारत में 141-बी-एचसीएफसी का उत्पादन होता नहीं है और आयात पर रोक के बाद ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली करीब 7800 टन गैस का उत्सर्जन घट जाएगा, जिसका बेसलाइन स्तर 2009-2010 होगा।

केंद्रीय वन एंव पर्यावरण मंत्रालय ने यह भी कहा है कि एचसीएफसी141-बी आयात रुकने पर एचसीएफसी उपभोग में 50 फीसदी की कमी होगी। हालांकि, यह नहीं बताया गया है कि यह 50 फीसदी की मात्रा क्या है और यह अनुमान किस आधार पर निकाला गया है। ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाले 7800 टन गैस उत्सर्जन में कटौती और 50 फीसदी उपभोग की कमी के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि एचसीएफसी 141बी की भूमिका कितनी है। क्या वाकई आयात पर रोक लगाने से एचसीएफसी उत्सर्जन में इतनी बड़ी कटौती संभव है?

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के ओजोन सेल और यूएन एनवॉयरमेंट ने ओजोन क्षरण तत्वों (ओजोन डिपलीशन सबस्टेंस झ ओडीपी) यानी एचसीएफसी को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए दस्तावेज तैयार किया था। इसमें कुल पांच एचसीएफसी गैस उपभोग का जो आंकड़ा दिया गया है उनमे दो नाम प्रमुख हैं, शेष का उपभोग न के बराबर हैं। पहला है एचसीएफसी 141-बी, दूसरा है एचसीएफसी-22।

यह ध्यान रहे कि ओजोन परत के लिए

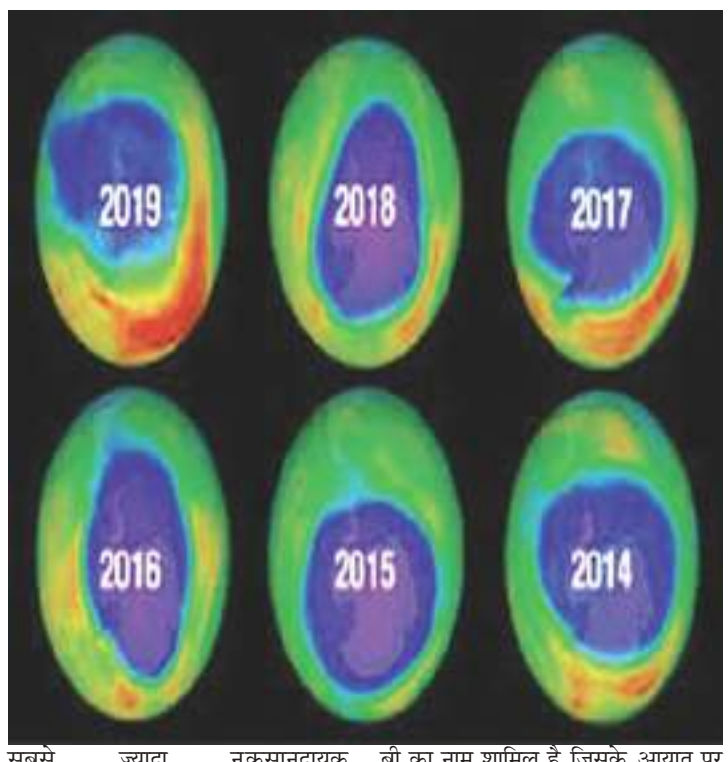

सबसे ज्यादा नुकसानदायक क्लोरोफ्लोरोकार्बन (सीएफसी) है। इसके बाद दूसरे स्थान पर एचसीएफसी है। अभी बात एचसीएफसी पर ही हो रही है। एचसीएफसी में देश में सबसे ज्यादा उपभोग एचसीएफसी-22 गैस का होता है। सरकार के मुताबिक सिर्फ इसका उत्पादन देश में किया जाता है और कई देशों को निर्यात भी किया जा रहा था। कुछ वर्ष ऐसे भी रहे हैं जिनमें एचसीएफसी-22 को थोड़ी मात्रा में आयात भी करना पड़ा है। प्रतिवर्ष इसका उत्पादन 09 हजार से 11 हजार टन के बीच है।

पर्यावरण मंत्रालय के दस्तावेज के मुताबिक एचसीएफसी 22 का 77 फीसदी इस्तेमाल कमरों में वातानूकलन के लिए रेफ्रिजरेंट्स के तौर पर किया जाता है। बाकी 14 फीसदी डक्टेड स्पलिट में किया जाता है। अब दूसरे स्थान पर एचसीएफसी 141 बी का नाम शामिल है जिसके आयात पर रोक लगाकर ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली गैस उत्सर्जन में बड़ी कटौती की बात कही जा रही है। हालांकि शोध पत्रों से सरकार के आंकड़े मेल नहीं खाते हैं।

2019 में एटमॉस्फेरिक केमेस्ट्री एंड फिजिक्स जर्नल में हालोकार्बन उत्सर्जन पर आधारित एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक भारत में एचसीएफसी के बारे में बहुत ही कम जानकारी मौजूद है। महज उपभोग के आंकड़े ही मौजूद हैं । भारत एचसीएफसी 141बी के उत्पादन आंकड़ों को रिपोर्ट नहीं करता है और न ही एचसीएफसी 141बी उत्पादन के लिए जांच या निगरानी तंत्र है।2019 में प्रकाशित इस शोधपत्र के मुताबिक दुनिया में एचसीएफसी की तीन प्रमुख गैसों का उत्सर्जन होता है। पहला एचसीएफसी 22, दूसरा एचसीएफसी 141बी और तीसरा एचसीएफसी 142बी। विकसित देशों में उत्सर्जन में गिरावट के कारण या तो इन गैसों का उत्सर्जन स्थिर है या फिर इनमें गिरावट जारी है। वहीं, भारत में प्रतिवर्ष एचसीएफसी141बी का उत्सर्जन एक हजार टन है। जबकि सरकार आयात रुकने के बाद 7800 टन उत्सर्जन घटने का दावा कर रही है। इसी शोध पत्र में कहा जा रहा है कि एचसीएफसी 22 का उत्सर्जन प्रति वर्ष करीब 8000 टन है। ऐसे में सरकार का दावा चकराने पर मजबूत करता है। यदि फैसला एचसीएफसी 141बी के आयात पर रोक का लिया गया है तो परिणाम एचसीएफसी 22 के कैसे आ सकते हैं?

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट के तरुण गोपालकृष्णन ने डाउन टू अर्थ को बताया कि भारत सरकार का उत्सर्जन संबंधी आंकड़े स्पष्ट नहीं हैं। न ही इनका संग्रह किया जाता है और नही इन्हें प्रकाशित किया जाता है। यदि सच में सरकार ने उत्सर्जन आंकड़ों में कटौती कर दी है तो हमें उत्सव मनाना चाहिए लेकिन सच्चाई यही है कि कटौती साबित हो यह बहुत ही टेढ़ी खीर है।

वहीं, आयात पर रोक लगाने के बाद यह भी संभव है कि एचसीएफसी का उत्पादन और इस्तेमाल करने वाली ऐसी सूक्ष्म और मध्यम औद्योगिक ईकाइयां इसका घरेलू स्तर पर इस्तेमाल चोरी-छुपे खुद से बढ़ा दें। यह इसलिए भी संभव है कि क्योंकि निगरानी और जांच के लिए कोई तंत्र नहीं है।

17-21 सितंबर, 2007 को 19वीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बैठक में संधि के अनुच्छेद-5 के तहत यह निर्णय लिया गया था कि एचसीएफसी उत्पादन और उपभोग को विकसित और विकासशील देशों से चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है।

वहीं इससे पहले जुलाई, 2002 में मॉन्ट्रियल प्रटोकॉल को लागू कराने वाली कार्यकारी समिति ने 37वीं बैठक में फोम सेक्टर में एचसीएफसी से भी ज्यादा घातक क्लोरोफ्लोरोकार्बन-11 (सीएफसी-11) को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए परियोजना को मंजूरी दी थी।

जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी पर्यावरण के लिए उपयोगी होते हैं जानवर

जंगल में पड़े किसी जानवर का शव, यह दृश्य कई लोगों को विचलित कर सकता है। लेकिन आंखों के लिए दुखदायी यह दृश्य अपने आसपास के प्राकृतिक वातावरण को खुशहाल बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। किसी जानवर का यह शव न केवल अन्य मांसाहारी जीवो को भोजन प्रदान करता है, बल्कि इसके साथ ही आस-पास उगने वाले पौधों के विकास में भी योगदान करता है। जोकि अनेक शाकाहारी जीवों और उनके शिकारियों को आकर्षित करता है।

यह अध्ययन इस कहावत को चरितार्थ करता है "जीवित हाथी लाख का और मरा सवा लाख का" जिसका अर्थ हुआ कि जीवित हाथी की उपयोगिता उसके मरने के बाद भी बनी रहती है और वह अनेकों रूप से प्रकृति में अपना योगदान देती है। यह अध्ययन जर्मन सेंटर फॉर इंटीग्रेटिव बायोडायवर्सिटी रिसर्च और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया है। जोकि अंतराष्ट्रीय जर्नल प्लोस-वन में प्रकाशित हुआ है।

पटना में बंद होंगे डीजल ऑटो

बिहार की राजधानी पटना में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार इन दिनों कई योजनाओं के साथ आगे आयी है। इन्हीं योजनाओं में से एक है पटना में चलने वाले ऑटो और कैब में डीजल और पेट्रोल इंजन के बदलकर उन्हें सीएनजी और बैटरी चालित बनवाना, ताकि इनसे कम से कम वायु प्रदूषण हो। इसके लिये परिवहन विभाग ने ऑटो और कैब मालिकों को 20 से 40 हजार रुपये तक कि प्रोत्साहन राशि देने की योजना शुरू की है। इसके तहत31 जनवरी 2021 तक राजधानी पटना में और 31 मार्च 2021 तक पटना से सटे दानापुर, खगौल, फुलवारी शरीफ के इलाकों में डीजल से चलने वाले ऑटो का परिचालन पूरी तरह प्रतिबंधित किया जा सके।

गांवों में भी देशी साग सब्जियों के स्वाद अब खो रहे हैं

अंकिता रासुरी

देश की अधिकांश आबादी गांव में रहती है, फिर भी शहरी संस्कृति को श्रेष्ठ समझा जाता है। 'गंवार' शब्द तो इतना गिर गया कि अक्सर 'बेवकूफ' के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। शब्दों के इस तरह के अर्थ प्राप्त करने की अपनी राजनीति होती है। गांवों से जुड़ी चीजों को जिन संदर्भों में इस्तेमाल किया जाता है, उनसे अक्सर हमें गावों की संस्कृति को कमतर समझे जाने का अहसास होता है। दरअसल यह गांव के वजूद, इसकी अस्मिता को हाशिये पर धकेलने का एक तरीका है। जबकि पर्यावरण और संस्कृति की दृष्टि से कई धरोहरों को गांवों ने ही सबसे ज्यादा संभालकर रखा हुआ है।

यह रोजगार की मजबूरी है कि लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। हालांकि, शहरी जीवन का अपना एक आकर्षण है, जिसके साथ आधुनिकता का बोध बहुत गहराई से जुड़ा है। रोजगार और शिक्षा की तलाश में मैं भी घर से बाहर हूं। समय मिलने पर जब भी उत्तराखंड में अपने गांव जाती हूं तो अपना गांव-बस्ती कहीं ज्यादा सुकून देने वाली शांत जगह लगती है। वहां रहते हुए कभी इस खूबी का अहसास नहीं हुआ। लेकिन यह एक बाहरी नजर है। पर्यटक भी इसी नजर से इन पहाड़ों को देखते हैं। इस नजर से सब कुछ खूबसूरत नजर आता है। विकास और आधुनिकता की दौड़ में गांव और इससे जुड़ी चीजों, बातों और खूबियों को अप्रासंगिक, पिछड़ी और दोयम दर्जे की करार देने वाली सभ्यता इन चीजों को अपने ड्राइंग रूम में सजाने की थोड़ी-सी दरियादिली जरूर दिखा देते हैं।

जब भी मुड़कर अपने गांव की ओर देखती हूं तो अपने आगे बढ़ने से ज्यादा एक भरे-पूरे समाज के पीछे छूट जाने का अहसास

मन में भर जाता है। वे लोग जो हर साल भूस्खलन, बाढ़ जैसी त्रासदियों की मार झेलते हुए भी बाहरी दुनिया को मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बड़े-बड़े बांधों की राह में खोखले हो चुके पहाड़ों पर बसे ये लोग पहाड़ से विशाल हृदय के साथ सबका स्वागत करते हैं। साल के आखिर में जब-जब वापस गांव का रुख करती हूं तो ये सवाल और भी तीखे होते जाते हैं। हर साल बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ पुराना पड़ जाता है। आज से 10-15 साल पहले तक जिन गांवों में हर घर में गाय, भैंस और बैल होते थे, किसी घर में मुश्किल से ही कोई जानवर नजर आता है। सौ से ज्यादा घरों के गांव में मुश्किल से 10-12 मवेशी हैं। हां, कुछ जगह 3जी या 4जी के सिग्नल पहुंचने लगे हैं, लेकिन मवेशियों से नाता टूटता जा रहा है। या कहें कि वक्त के साथ लोगों की जरूरतें और प्राथमिकताएं बदल रही हैं।

मेरे लिए इस तरह के बदलाव आधुनिक अर्थव्यवस्था या विकास के आधुनिक मॉडल के साये में पनप रही इकहरी संस्कृति के प्रसार की निशानियां हैं। गांव के लोग भी दूध-दही-मट्ठे के लिए बाजार पर उसी तरह निर्भर होने लगे हैं, जैसे शहरों में होते हैं। गांव में किसी के यहां ज्यादा दूध-दही हो तो मक्खन और घी के लिए एडवांस में ही पैसे दे दिए जाते हैं। इसके लिए भी बारी का इंतजार करना पड़ता है। गांव से गांव वाली चीजों को ही इस तरह ओझल होते देखना एक अलग किस्म की पीड़ा और आश्चर्य की बात है।इस बार काफी दिन बाद घर जाना हुआ तो घर की हरी सब्जी राई और सरसों खाने का बहुत मन था। कुछ अपने घर की तो कुछ चाचियों-भाभियों द्वारा दी गई। लेकिन खाने के बाद वह उत्साह अजीब निराशा में बदल गया। पहले होता यह था इन सब्जियों की खुशबू खींच ले जाती थी। अब ना सब्जी में खुशबू थी, ना पहले वाला स्वाद। पता चला कि गांव के लोगों ने खेतों में गोबर/राख डालना लगभग छोड़ दिया है। मवेशियों के घटने से गांवों में प्राकृतिक खाद की भी कमी होने लगी है और यूरिया जैसी उर्वरकों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है। मुझे सब्जियों से गुम स्वाद और सुगंध की वजह तलाशने में देर नहीं लगी। न ही इसके लिए पूरी तरह गांव के लोगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तरक्की और आधुनिकता की जो समझ हाल के वर्षों में विकसित हुई है, यह उसी की देन है? दरअसल, गांव वही सीख रहे हैं, जिसे शहरों ने श्रेष्ठ और सही साबित किया है।

हटिया रेल मंडल का आमंत्रण

रांची : 71 वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर दुर्गा पूजा मैदान, हटिया रेलवे कॉलोनी प्रांगण में दिनांक 26 जनवरी 2020, प्रातः 9:15 बजे मंडल रेल प्रबंधक श्री नीरज अंबष्ठ द्वारा ध्वजारोहण समारोह संपन्न होगा। इस अवसर पर आप सादर आमंत्रित हैं।

सीसीएल में कोल क्षेत्र पर सेमिनार का आयोजन

रांची :देश की उर्जा आवश्यकता में कोल इंडिया का योगदान व भारत सरकार के सहयोग पर चर्चा जनसम्पर्क विभाग द्वारा सीसीएल मुख्यालय, दरभंगा हाउस, रांची के एचआरडी विभाग में देश की उर्जा आवश्यकता में कोल इंडिया का योगदान व भारत सरकार के सहयोग विषय पर सेमिनार आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता आलोक सिंह ने देश में उर्जा के भविष्य एवं आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि देश व विश्व का सबसे बड़ा कोल उत्पादक है और भविष्य में भी वह देश की उर्जा आवश्यकता को पूरा करता रहेगा।

आलोक सिंह ने देश की उर्जा आवश्यकता में कोयला की अहम भूमिका एवं कोयला मंत्रालय एवं भारत सरकार के अन्य मंत्रालय के सहयोग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि देश में हो रहे कोयला आयात को कम करते हुये आने वाले समय में शुन्य करना है। इस संदर्भ में माननीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी व भारत सरकार का पूर्ण सहयोग मिल रहा है जो सराहनीय है। माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी एवं उनकी टीम सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी कोल इंडिया एवं सीसीएल सहित अन्य अनुषंगी कंपनियों को मजबूत बनाने एवं उसका विस्तार करने के लिए निरंतर कटिबद्ध है। सीसीएल के सीएमडी गोपाल सिंह का मानना है कि समाज के सर्वागींण विकास में शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इस दिशा में सीसीएल बच्चों के भविष्य को संवारने में अनेकों पहल किये हैं जिससे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके।

माननीया राज्यपाल नई दिल्ली में 22 जनवरी को केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फगन सिंह कुलस्ते को पुष्पगुच्छ देते हुए

नैनोमेडिसिन से बढ़ रहा है पर्यावरण और जीवों को खतरा

एजेंसियां : स्विस फेडरल लैबोरेट्रीज फॉर मैटेरियल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी (एम्पा) के शोधकर्ता वर्तमान में नैनोमेडिसिन के खतरों के बारे में पता लगा रहे हैं। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जीवों, मनुष्यों और पर्यावरण को नैनोमैटिरियल्स से होने वाले खतरों का आकलन किया है। वर्तमान में कई ऐसी दवाएं है, जो नैनोमैटिरियल्स के उपयोग से बनाई जा रही हैं। जैसा कि पहले से सर्वविदित है कि वातावरण में फैले दवाओं के कणों से पशुओं में हार्मोन बदल सकते है। पक्षी के अंडों पर नैनो कणों की पतली परत चढ़ जाती है, जिससे उनका विकास रुक सकता है। नैनो मेडिसिन के पानी में मिलने पर मछली में प्रजनन संबंधी विकार हो सकते है, और ऊदबिलाव की जनसंख्या में गिरावट आ सकती है। यह अध्ययन जर्नल ऑफ नैनो बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ है।

छोटे कण, बड़े काम

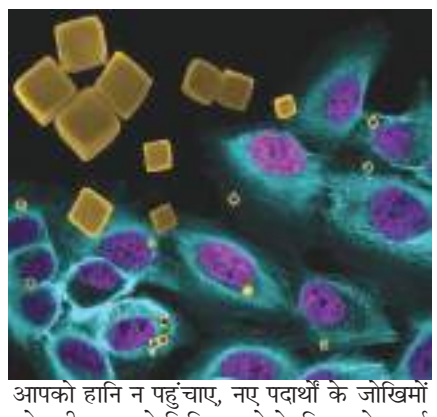

दूसरी ओर, नैनोमेडिसिन पहले से ही नई दवाओं के साथ आशा के अनुरूप परिणाम दे रहे है। नैनो-हीरे के उपयोग से चिकित्सक रक्त-मस्तिष्क की बाधा पर काबू पा रहे हैं, और सोने के नैनोकणों के साथ वे कैंसर के उपचार करने में मदद कर रहे हैं। इन नैनोकणों के लिए कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं है। इस तरह पर्यावरण में जारी होने वाले नैनो-सामग्री के खतरों के बारे में बहुत कम जानकारी हैं। एक अत्याधिक खतरनाक पदार्थ जिसके संपर्क में आप आते हैं, जो आपको हानि पहुंचा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह पदार्थ आपको हानि न पहुंचाए, नए पदार्थों के जोखिमों को सटीक रूप से चित्रित करने के लिए, शोधकर्ता पहले थ्रेशोल्ड मान निर्धारित करते हैं। जिस पर पदार्थ का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, साथ ही साथ अपेक्षित मात्रा जो पर्यावरण में जारी की जाती है। इन आंकड़ों को जानना आसान नहीं है, क्योंकि शरीर में मौजूद दवा अपशिष्ट के रुप में बाहर निकलती है जो वेस्टवाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से नदियों और झीलों में चली जाती है। इस तरह यह वातावरण में फैल जाते है। सबसे पहले इसे निर्धारित किया जाना चाहिए।कणों के एक बार पर्यावरण में जारी होने के बाद, ये पॉलिमर को जैविक या भौतिक-रासायनिक अपघटन द्वारा छोटे घटकों में बदल देते हैं। नोवाक कहते हैं कि अधिकांश नैनोमैटिरियल्स के कणों की मात्रा जारी होने के बारे में कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है।

अपनी जिम्मेवारी के साथ आपका बेटा आपके समक्ष खड़ा है: हेमंत सोरेन

संवाददाता

बोकारो/रांची:जिस उद्देश्य के लिए हम झारखंड की सत्ता में आये हैं। जिन उद्देश्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी आप सभी ने सौंपी है उन आकांक्षाओं और उद्देश्यों को वर्तमान सरकार अवश्य पूरा करने का प्रयास करेगी। इस लक्ष्य को भेदने के लिए युवा वर्ग आगे बढ़ेगा। आपके आगे बढ़ने से ही राज्य, समाज और परिवार की समृद्धि बढ़ेगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री बोकारो में आयोजित सभा कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे।

भौतिकतावादी युग में सभी संसाधन उपलब्ध हैं फिर भी अमन, चैन और शांति की कमी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि बोकारो में मेरा बचपन गुजरा। पढ़ाई यही हुई। बोकारो में मैंने महत्वपूर्ण समय गुजारा है। अपनी जिम्मेवारी के साथ आपका बेटा आज आपके समक्ष खड़ा है। इस भौतिकवादी युग में सभी संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी अमन, चैन और शांति की कमी है। जीवन में शांति का संचार हो, इसके लिए प्रभु के विचारों के साथ चलना होगा, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना होगा। भौतिकतावादी युग में परंपरा, व्यवस्था के साथ जीएं। मजबूत विचार के साथ आगे बढ़ें। आज के कार्यक्रम से आप सभी को केवल लाभ ही होगा।

कोरोना वायरस को लेकर झारखंड भी अलर्ट पर

संवाददाता

स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार ने कोरोना- वायरस के सतत निगरानी हेतु जारी की एडवाइजरी

राज्य में कोरोना- वायरस का कोई मामला नहीं हुआ है-नितिन मदन कुलकर्णी, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग

रांची :स्वास्थ्य विभाग, झारखण्ड सरकार नियमित रूप से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा कोरोना-वायरस के संबंध में जारी की जा रही एडवाईजरी/ रडढर अपडेट, दिशा निर्देशों की समीक्षा कर रहा है। सभी जिलों तथा स्वास्थ्य संस्थानों को इस संबंध मे निर्देश दिया गया है। साथ ही, समाचार पत्रों एवं मीडिया में इस रोग से संबंधित प्रकाशित सूचनाओं को अध्ययन तथा समीक्षा कर हालात की निगरानी की जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नीतिन मदन कुलकर्णी ने संबंधित राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात पर कड़ी नजर रखने का निदेश दिया है। कोरोना- वायरस के निगरानी हेतु राज्य सर्विलांस पदाधिकारी को राज्य नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है। प्रधान सचिव ने कहा कि State Epidemiologist भारत सरकार के EMR Division /केन्द्रीय निगरानी ईकाई, नई दिल्ली एवं अन्य संस्थानों के साथ सभी जिलों के स्वास्थ्य संस्थानों से निरंतर संपर्क में रहेंगे।

स्वास्थ्य विभाग ने e-Mail के माध्यम से सभी जिलों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित SOPs, Advisory, Reporting Formats तथा दिशा निर्देश साझा किया है, जिसके अनुसार सभी जिला सर्विलांस इकाई को इस रोग से संबंधित समीक्षा, निगरानी, संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तैयारी रखने के लिए निदेश दिया गया है। विभाग ने Integrated Disease Surveillance Program (IDSP) द्वारा विकसित प्रतिवेदन प्रपत्र (Reporting Formats) सभी जिलों तथा स्वास्थ्य संस्थानों को भेजा है ताकि जिले इस रोग के प्रति सतर्क रहे, रोग की रिपोर्ट करें और संदिग्ध मामलों की लगातार 28 दिनों तक निगरानी करें।

सूचना भवन में हुआ मतदाता दिवस का शपथ कार्यक्रम

संवाददाता

रांची : सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के निदेशक राम लखन प्रसाद गुप्ता ने सूचना भवन के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई। ज्ञात हो कि मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त है कि 25 जनवरी को शनिवार होने के कारण विभाग में छुट्टी रहेगी इस कारण 24 जनवरी को ही मतदाता दिवस हेतु शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

लखन प्रसाद गुप्ता ने सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को शपथ दिलाया कि "हम, भारत के नागरिक, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर, धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगें"। इस अवसर पर विभाग के उप सचिव, अवर सचिव, सभी उप निदेशक, सभी सहायक निदेशक, सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

खोज: फ्लोराइड युक्त जल के शोधन के लिए नया संयंत्र

एजेंसियां : सीएमईआरआई के शोधकर्ताओं ने एक सामुदायिक वाटर डिफ्लुरिडेशन संयंत्र बनाया है, जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों और फ्लोराइड युक्त जल का शोधन करता है। भू जल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में 6.6 करोड़ लोग फ्लोरोसिस के शिकार हैं, जिनमें फ्लोरोसिस से ग्रस्त करीब 60 लाख बच्चे भी शामिल हैं। भारतीय शोधकर्ताओं ने फ्लोराइड युक्त जल को पीने योग्य बनाने के लिए एक सामुदायिक संयंत्र विकसित किया है, जो फ्लोराइड ग्रस्त इलाकों में फ्लोराइड को भूमिगत जल से अलग करने में उपयोगी हो सकता है।पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर स्थित केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई) के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया यह सामुदायिक वाटर डिफ्लुरिडेशन संयंत्र है। इसका विकास हानिकारक सूक्ष्मजीवों और फ्लोराइड युक्त जल के शोधन के लिए किया गया है। इस संयंत्र को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है यह नई तकनीक पानी में फ्लोराइड के स्तर को उसकी शुरुआती मात्रा से सात गुना तक कम कर सकती है। इस तरह साफ किए गए पानी का उपयोग सुरक्षित पेयजल के रूप में करके फ्लोराइड के खतरे से बचा जा सकता है। यह सामुदायिक डिफ्लुरिडेशन संयंत्र बहु-चरण गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। इसमें लगे कार्ट्रिज में रेत एवं बजरी के साथ-साथ वैज्ञानिकों द्वारा संशोधित बहुआयामी उपयोग वाले अन्य प्राकृतिक अवशोषकों का उपयोग किया गया है। एक हजार लीटर की भंडारण क्षमता वाले यह संयत्र एक घंटे में 700 लीटर स्वच्छ पेयजल प्राप्त किया जा सकता है। इस संयंत्र की एक खास बात यह है कि इसके संचालन के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती और इसे मार्क-क्क से जोड़ा जा सकता है। इस संयंत्र के संचालन के लिए किसी विशेष कौशल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। दूषित जल को हैंड पंप के जरिये एक ओवरहेड टैंक में जमा किया जाता है। एक पाइप की मदद से दूषित जल ड्रम के आकार के शोधन संयंत्र के ऊपरी हिस्से में प्रवाहित किया जाता है। इसमें फव्वारे की तरह एक उपकरण लगाया गया है, जो पानी को समान रूप से वितरित करने में मदद करता है। ड्रम की भीतर अवशोषकों की पांच स्तरीय परतें बिछी रहती हैं, जो फ्लोराइड युक्त जल के शोधन में मदद करती हैं। संयंत्र में विशेष आकार की बजरी, शुद्ध सिलिका, फेराइट से संतृप्त एक्टिवेटिड एल्युमिना, जिंक युक्त एक्टिवेटिड बायोचारकोल और एक अन्य बजरी की परत बिछाई जाती है। इस संयंत्र की तकनीक को पांच कंपनियों को नॉन एक्सलूसिव आधार पर हस्तांतरित किया गया है।

उपविकास आयुक्त ने की आइटीडीए की समीक्षात्मक बैठक

- लापरवाही बरतने वालों को दिया कठोर निदेश
- कहा, "प्रखंडवार डेली रिपोर्ट भेजेंगे पदाधिकारी, डाटा करेक्शन ससमय करें पूरा
- लाभुकों को ससमय लाभ पहुंचाना करें सुनिश्चित

संवाददाता

रांची :उप विकास आयुक्त-सह-निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण, रांची अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला एवं प्रखंड स्तर के संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई। आयोजित बैठक में जनजातीय विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उप विकास आयुक्त मित्तल ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, एकलव्य स्कूल पंजीकरण आदि की समीक्षा के लिए सभी ब्लॉक और जिला स्तर के अधिकारियों से जानकारी ली। बैठक के दौरान उन्होंने उन्होंने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नामांकित लाभार्थियों की रिपोर्ट की समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान, उन्होंने संबंधित अधिकारियों से डेटा सुधार में देरी के कारण के बारे में पूछा। जिसके जवाब में संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने पर श्री मित्तल ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा,"ITDA के तहत विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने में देरी और लापरवाही के बारे में चेतावनी दी। सभी अधिकारियों को निदेश देते हुए उन्होंने प्रखंडवार एक दैनिक रिपोर्ट भी मांगी है।

डीएवी शिक्षादीप हेहल का वार्षिक समारोह मनाया गया

रांची : 25 जनवरी को डीएवी शिक्षादीप हेहल प्रांगण में विद्यालय का वार्षिक समारोह का आयोजन संपन्न हुआ। मौके पर मुख्य अतिथि

न्यायाधीश स्थायी,लोक अदालत झारखण्ड मिस्टर बी एन रॉय, छोटानागपुर खादी ग्राम उद्योग भंडार, तिरील आश्रम के मंत्री ए के चौधरी महावीर मण्डल जयप्रकाश नगर के अध्यक्ष अनिल यादव, छात्र कलब ग्रुप के अध्यक्ष शिव किशोर शर्मा, निदेशक शिवनंदन पाठक मौजूद थे। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्राचार्य राजेश कुमार, शिक्षिका सुग्गी महतो के निर्देशन में नाटक, छोटानागपुरी नृत्य, रामायण पाठ आदि पेश किया जिसे अतिथियों ने भरपूर सराहा। शिवनंदन पाठक ने कहा बच्चो के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में हर वर्ष इस प्रकार के महोत्सव मनाये जाते है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अविनाश कुमार सिंह, ब्रजेश कुमार पाठक, अजय कुमार मिश्रा, प्रभाष गौरव, कुनाल कौशल पाठक, अनु आस्था, अंकित अर्णव, नवीन कुमार आदि विद्यालय कर्मचारियों का मुख्य योगदान रहा ।

विस्थापितों की समस्याओं के निष्पादन के लिए सीसीएल प्रतिबद्ध -सीएमडी सीसीएल

......*पेज 1 का शेष*

गोपाल सिंह ने जोर देते हुए कहा। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के बेहतरी के लिए कृतसंकल्पित है। श्री सिंह ने कहा कि विस्थापितों हेतु सीसीएल द्वारा शिक्षा, रोजगार, पेयजल, स्वास्थ्य, खेल, पर्यावरण पर विशेष बल देते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि सीसीएल हर विस्थापित गांव में 5-10 सदस्य समिति बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। यह समिति पुनस्र्थापना स्थल का चयन करेगी और सीसीएल वहॉ सभी सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए विकसित करेगा। उन्होंने पुनः कहा कि सीसीएल की प्राथमिकता ''गरीब, ग्रामीणों एवं श्रमिकों का सर्वागींण विकास'' है ।

गोपाल सिंह ने कहा कि देश के हर 100 बल्ब में 72 बल्ब हमारे कोयले से उत्पादित बिजली से जलते हैं। उन्होंने कहा कि माननीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी के कुशल मार्गदर्शन में सीसीएल देश की उर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है और 2023-24 तक हम 100 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। माननीय श्री जोशी सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनी कोल इंडिया एवं सीसीएल सहित अन्य अनुषंगी कंपनियों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है जिसके लिए हम सब अभारी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से भी हमेसा सहयोग मिलता आ रहा है।

बैठक के दौरान उपस्थित समिति सदस्यों ने अपनी एवं गांव की समस्याओं को सीसीएल प्रबंधन के समक्ष रखा जिसे सीएमडी श्री गोपाल सिंह ने एक-एक कर सुना और उपस्थित अधिकारियों को उसके निदान हेतु दिशा-निर्देश भी दिये। ज्ञातव्य हो कि सीएमडी श्री गोपाल सिंह की पहल पर सीसीएल प्रबंधन द्वारा सभी कमांड क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों एवं सदस्यों हेतु समस्याओं के निष्पादन हेतु प्रत्येक गांव में समिति स्थापित की जा रही है। कमांड क्षेत्र के परियोजना पदाधिकारी एवं क्षेत्रिय महाप्रबंधकों के साथ नियमित बैठक की जायेगी। साथ ही क्षेत्रिय प्रबंधन जिला प्रशासन से विस्थापितों के विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु सहयोग भी करेगा।

निदेशक तकनीकी (संचालन) श्री वी.के. श्रीवास्तव, निदेशक तकनीकी (योजना/परियोजना) श्री भोला सिंह ने विस्थापितों से कहा कि सीसीएल प्रबंधन सदैव आपके साथ है और आपकी समस्याओं के निपटरा हेतु सकारात्मक रूप से तत्पर है। कार्यक्रम के सफल आयोजन में भूमि एवं राजस्व विभाग का सक्रिय योगदान रहा।

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

● Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

फोटो न्यूज

गुणों की वजह से खैर के पेड़ों पर वन माफिया की नजर, सिमट रहा जंगल

एजेंसियां : देशभर से आए दिन खैर की लकड़ी तस्करी की खबरें आती रहती हैं। औषधीय गुण, कत्था बनाने और चमड़ा उद्योग में उपयोगिता के लिए मांग तेज होने की वजह से खैर की प्रजाति पर संकट आ गया है। देशभर में खैर का जंगल तेजी से सिमट रहा है और वन विभाग ने इसे दुर्लभ वृक्ष की श्रेणी में रखा है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में पेड़ों की प्रजातियों को संतुलित रूप से इस्तेमाल में लाने की बात कही गई है जिससे वे खत्म न हों।अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (IUCN) ने वर्ष 2004 में विश्व में तकरीबन 552 पेड़ों की प्रजातियों को खतरे में माना गया जिसमें 45 प्रतिशत पेड़ भारत से थे। इन्हीं में खैर का नाम भी शामिल है। इस पेड़ का इस्तेमाल औषधि बनाने से लेकर पान और पान मसाला में इस्तेमाल होने वाले कत्था, चमड़ा उद्योग में इसे चमकाने के लिए किया जाता है। प्रोटीन की अधिकता के कारण ऊंट और बकरी के चारे के लिए इसकी पत्तियों की काफी मांग है। चारकोल बनाने में भी इस लकड़ी का उपयोग होता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल डायरिया, पाइल्स जैसे रोग ठीक करने में होता है। मांग अधिक होने की वजह से खैर के पेड़ों को अवैध रूप से जंगल से काटा जाता है।

तस्करी के मामलों में पुलिस व वन विभाग द्वारा वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 की धारा 50 के अंतर्गत गिरफ्तारी करके कार्रवाई होती है। तस्करों के पकड़े जाने पर तीन वर्ष की सजा व जुर्माने का भी प्रावधान है।

कम हो रहे खैर के जंगल

आए दिन देश के हर कोने से वन विभाग द्वारा ऐसे तस्करों को पकड़ने की खबरें आती है। वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक अकेले मध्यप्रदेश मसान पिछले पांच महीनों में 20 हजार खैर के पेड़ काट दिए गए। दूसरे राज्यों से आए दिन तस्करी की खबरें आती रहती है। हालांकि, कितना जंगल कम हुआ है इसका ठोस आंकड़ा वमन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हरयाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़ खैर तस्करी के प्रमुख केंद्र बन रहे हैं।

यह है कानूनी तरीका

खैर के हरे पेड़ को काटने की सख्त मनाही है। उत्तराखंड में नदियों के किनारे लगे पेड़ जो बाढ़ में बह जाते हैं, उन्हें वन विभाग बेचता है। इसी तरह अन्य स्थानों पर भी वन विभाग खराब हुई पेड़ों को बेचते है, जिससे बाजार में इसकी उपलब्धता के साथ जंगल भी बचाया जा सके। हरयाणा में हर 10 साल में वन विभाग खैर के वयस्क पेड़ काटते हैं और नया पौधा लगा देते हैं। मांग अधिक होने की वजह से वन तस्कर बेहताशा इस पेड़ को काटते हैं। बाजार में लकड़ी की कीमत 5000 से 10 हजार रुपए प्रति क्विंटल तक है। इस तरह एक वयस्क पेड़ से 5 से 7 लाख रुपए तक का फायदा हो जाता है।

पहली बार सामने आया जंगल का आंकड़ा

वन विभाग के मुताबिक किसी जंगल में 25 प्रतिशत से अधिक खैर के पेड़ हों तो उसे खैर का जंगल माना जाता है। लगातार कटाई की वजह सर और नए पेड़ न लगाने की वजह से जंगल लगातार सिमट रहे हैं। हालिया वन सर्वेक्षण में पहली बार खैर के जंगल

कहां कितना खैर

राज्य- खैर वन का प्रतिशत	
असम- 0.08	जम्मू कश्मीर और लद्दाख- 0.12
हिमाचल प्रदेश- 0.01	मध्यप्रदेश- 1.67
बिहार-0.06 %	राजस्थान- 1.52
पंजाब- 0.23	असम- 0.08
पश्चिम बंगाल - 1.18	उत्तराखंड- 0.97
	उत्तरप्रदेश- 1.08

(स्त्रोत- वन सार्वेक्षण2019)

आकार बदलने लगे हैं नदियों के डेल्टा

एजेंसियां : एक नए अध्ययन में बताया गया है कि कैसे दुनिया भर में नदियों का डेल्टा का आकार बदल रहा है। अध्ययन में इसके लिए इंसानी गतिविधियां और जलवायु परिवर्तन को दोषी माना गया है। हालांकि इन बदलते डेल्टाओं के नुकसान और फायदे दोनों है। डेल्टा उस भूभाग को कहा जाता है, जो नदियों द्वारा लाई गई गाद (सेडमन्ट) से बनता है। यह मुख्यतः नदी के उस मुहाने पर बनता है, जहां वह किसी समुद्र अथवा झील में गिरती है। इस भूभाग का आकार आम तौर पर त्रिभुजाकार होता है। नदियों के डेल्टा पृथ्वी पर सबसे अधिक आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से बेशकीमती है। समुद्र के स्तर में वृद्धि न होने पर भी डेल्टाओं पर खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से चरम मौसम की घटनाएं बढ़ रही हैं। इससे गाद (सेडमन्ट) के प्रवाह में परिवर्तन होता हैं, जो डेल्टा की आकृति को प्रभावित करती हैं, जिसमें डेल्टा का कटाव भी शामिल है। यह अध्ययन नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। डच और अमेरिकी टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन में तुलाने विश्वविद्यालय के शोधकर्ता शामिल हैं। शोधकर्ताओं ने दिखाया कि नदी का प्रवाह, लहरों और ज्वार कैसे नदी के मुहाने और उनके संबंधित डेल्टा के आकार को बदल सकते हैं। इससे भूमि को लाभ और नुकसान दोनो हो सकते है। अध्ययन से पता चलता है कि विश्व स्तर पर कई डेल्टा आज भी भूमि का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन समुद्र के स्तर में वृद्धि और अन्य मानवीय गतिविधियों के कारण इस दौर के जारी रहने की संभावना कम है। दुनिया भर में लगभग 11,000 डेल्टा है। इन डेल्टाओं के सहारे, वर्तमान में उपलब्ध वैश्विक डेटासेट की मदद से नदी के जल निकासी घाटियों, गाद के प्रवाह, लहर, जलवायु और ज्वार की रेंज की जानकारी हासिल की जा सकती है।

टोबाने में वोग्स जियोलॉजी प्रोफेसर और सह-अध्ययनकर्ता टॉब्जन ने कहा कि, इस अध्ययन के रोमांचक पहलुओं में से एक यह है कि, यह नए विकसित सिद्धांत के आधार पर डेल्टा के आकार का पूर्वानुमान लगाने का सबसे बेहतर तरीका प्रदान करता है। नीदरलैंड में यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय में एक सहायक प्रोफेसर और प्रमुख अध्ययनकर्ता जैप निएनहुइस ने सिद्धांत के उस हिस्से को विकसित किया है, जो डेल्टा पर ज्वार के प्रभाव का पूर्वानुमान लगाता है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में विकसित उपकरण का उपयोग किया, जिसे एक्वा मॉनीटर के रूप में जाना जाता है। इसकी सहायता से सैटेलाइट इमेजरी से पिछले 30 वर्षों में भूमि को हुई हानि और लाभ के बारे में जाना जाता है। इससे पता चलता है कि मिसिसिपी डेल्टा सहित दुनिया भर में लगभग 1,000 डेल्टाओं का कटाव हो रहा है। लगभग 1,500, डेल्टा अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित हैं।

नदियों से बहने वाले बढ़े हुए गाद के कारण डेल्टा बढ़ रहे हैं। यह मुख्य रूप से वनों की कटाई के कारण हो रहा है, वनों की कटाई भूमि के कटाव की दर को बढ़ाता है। यह अध्ययन ऐसी जानकारी भी प्रदान करता है, जिसमें अलग-अलग क्षेत्रों के लोग जो विशेष रूप से भूमि निर्माण में रुचि रखते है, जैसे मिसिसिपी डेल्टा - जहां तटीय भूमि के पुनर्निर्माण की तलाश की जा रही है। नई भूमि के प्रत्येक वर्ग फुट बनने के लिए औसतन, लगभग 150 घन फीट गाद की जरूरत होती है। 1 फीसदी डेल्टा से 30 फीसदी भूमि क्षेत्र बढ़ता है। ●

एकजुटता भारत को पूरी दुनिया में ताकतवर बनायेगा

हेमंत सोरेन ने राज्य की सवा तीन करोड़ जनता को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं।

रांची :यह दिन हमें वीर शहीदों को नमन करने का मौका देता है। यदि हम उनके आदर्शों को अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो पुनः हमारे अंदर वही उर्जा का संचार होगा, जिसकी आवश्यकता हमारे देश, राज्य और समाज को है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री दुमका के इन्डोर स्टेडियम में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है। यहां के हर वर्ग के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यह एकजुटता बरकरार रहेगी और भारत पूरी दुनिया में एक बड़ी ताकत के रूप में जाना जाएगा। इतना ही नहीं हमारे देश की एकता पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनेगी।

वीरों की धरा है अपना झारखण्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतिहास इस बात का गवाह है कि झारखंड वीरों की भूमि रही है। यहां के वीरों ने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमें इस बात का गुमान है कि हम इस वीर भूमि के निवासी हैं, जिन्होंने इस देश, समाज, संस्कृति और धरोहर की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी थी। भगवान बिरसा मुण्डा, सिदो- कान्हू चांद -भैरव और फूलो- झनो जैसे सैकड़ों वीरों ने देश की आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था और हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए थे कमुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन ने इन वीर शहीदों को नमन करते हुए कहा कि उनके सपनों का झारखंड बनाने के लिए सरकार कृतसंकल्पित है।

जबतक दुनिया रहेगी गणतंत्र दिवस का वजूद रहेगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में नई सरकार बनने के बाद यह पहला मौका मिला है। जब हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं। पूर्व की तरह हमें इस दिन और भी यादगार बनाना है। भारत में कुछ तारीख ऐसी हैं जिसका वजूद तब तक रहेगा जब तक दुनिया रहेगी। इसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन सबसे खास मायने रखता है। इस दिन को हम कभी भुला नहीं सकते हैं। दुमका उपायुक्त श्रीमती बी राजेश्वरी ने कहा कि पुस्तकों के प्रति मुख्यमंत्री का लगाव इस बात का इशारा करता है कि ज्ञान ही वह ताकत है, जिसके जरिए देश और राज्य को विकास के रास्ते पर बेहतर तरीके से आगे ले जाया जा सकता है।

गणतंत्र की शुभकामनाओं के साथ
श्री साईं अलुमिनियम एंड फैब्रिकेशन
कटहल मोड़ राँची, नजदीक डी ए वी, हेहल, मो. 9608195560

अलुमिनियम विन्डो एवं स्टील वर्क

Quality With डेमोडिसिन्स
आप के प्यारे पेट्स पशुधन, जानवरों की सारी दवाईयां, वेक्सिन फूड एवं सभी एक्सेसरीज उपलब्ध
रातू रोड, नियर मेट्रो गली रांची
फोन :9334935339

दयानन्द आर्य विद्या पब्लिक स्कूल
कमड़े /माण्डर,राँची-1
गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से समस्त झारखण्ड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
निदेशक - राजेश दत्त

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : JHAHIN/2019/78094, email:greenrevolt2019@gmail.com. ☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।